लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1166
11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तकनीकी वस्त्र पार्क

1166. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः
श्री दरोगा प्रसाद सरोजः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित तकनीकी वस्त्र पार्क का महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र के उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कौडगांव और उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एमआईडीसी के तकनीकी वस्त्र पार्क स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार ने आकांक्षी जिले होने कि वजह से उस्मानाबाद और आजमगढ़ में रोजगार सृजन के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी है:

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ज): वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों में 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह उम्मीद की जाती है कि पूरा होने पर प्रत्येक पीएम मित्र पार्क से 3 लाख (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दोनों) रोजगार उत्पन्न होंगे।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों से अपने-अपने राज्यों में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। जवाब में, महाराष्ट्र (औरंगाबाद और अमरावती) से दो और उत्तर प्रदेश (लखनऊ) से एक सहित 13 राज्य सरकारों से 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए। सरकार ने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अमरावती, महाराष्ट्र और लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक-एक साइट सहित 7 साइटों को अंतिम रूप दिया है।

पीएम मित्र पार्क कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और छपाई से लेकर गारमेंट विनिर्माण, सहायक उपकरण निर्माताओं तक एक ही स्थान पर एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे लॉजिस्टिक और लेनदेन लागत कम होगी। मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) और तकनीकी वस्त्र इन पार्कों में नए निवेश का एक महत्वपूर्ण घटक होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तकनीकी वस्त्र पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में लंबित नहीं है।

मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण (एससीबीटीएस) के लिए (समर्थ) योजना को भी लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य संगठित वस्त्र (कताई और बुनाई को छोड़कर) और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित और पूरक करने और पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल और कौशल उन्नयन प्रदान करने के लिए मांग संचालित, रोजगार उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है। दिनांक 03.02.2025 तक, कुल 3,57,949 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया जा चुका है और 2,86,206 लाभार्थियों को "समर्थ" के तहत रोजगार प्रदान किया गया है।

इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं/पहलों को कार्यान्वित कर रहा है। प्रमुख योजनाएं/पहलें इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम), जिसे देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था; बेंचमार्क टेक्सटाइल मशीनरी में योग्य निवेश के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एटीयूएफएस; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों आदि के लिए शुरू से अंत तक समर्थन के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)।

महाराष्ट्र एकीकृत और सस्टेनेबल वस्त्र नीति वर्ष 2023-28 तकनीकी वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करती है जिसमें पूंजी सब्सिडी, ईटीपी, सीईटीपी, जेडएलडी और सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए समर्थन शामिल है। यह नीति सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने को भी प्रोत्साहित करती है।

इस नीति के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में छह तकनीकी वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए सभी क्षेत्रों में समान सब्सिडी सहायता के साथ कई तरह के प्रोत्साहन आरंभ किए हैं।

उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति वर्ष 2017 और वर्ष 2022 के अनुसार, राज्य सरकार राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

***